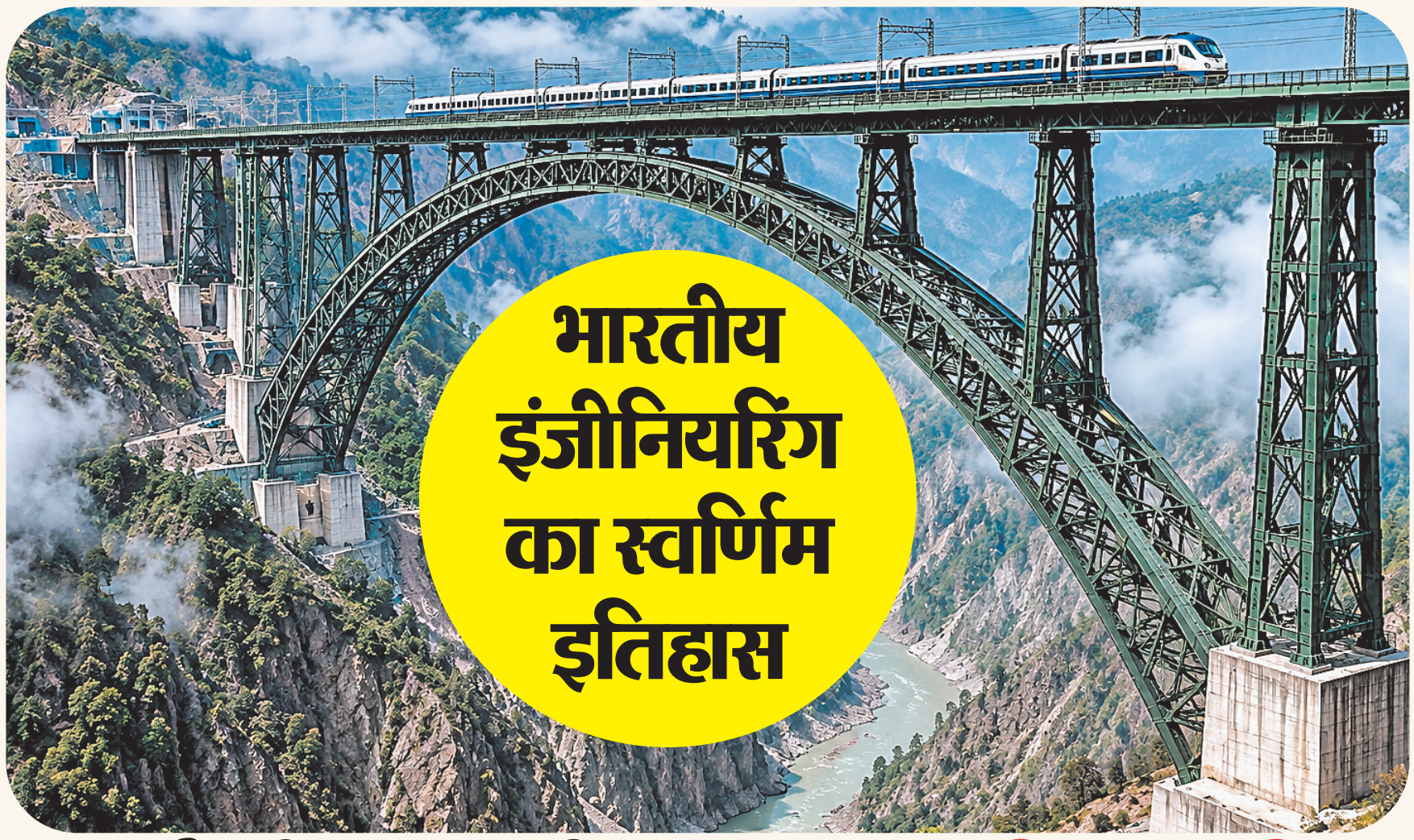

पहाड़ों से जंग जीतकर बना चिनाब ब्रिज

डॉ. शिशिर उपाध्याय, चिनाब ब्रिज, जम्मू से

रियासी (जम्मू-कश्मीर)। चिनाब नदी की गहरी खाई के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल केवल लोहे और कंक्रीट की संरचना नहीं है, बल्कि यह भारतीय इंजीनियरों के साहस, धैर्य और तकनीकी कौशल की ऐसी गाथा है, जिसने विश्व पटल पर भारत की एक नई पहचान स्थापित की है। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार से कई गुना अधिक ऊंचाई वाला चिनाब ब्रिज आज देश के गौरव का प्रतीक बन चुका है। चिनाब ब्रिज को बनाने की मंजूरी वर्ष 2003 में मिली थी। प्रारंभिक लक्ष्य इसे 2009 तक पूरा करने का था, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों, डिजाइन में बदलाव और मौसम की मार के कारण इसे पूरा होने में लगभग 22 वर्ष लग गए। यह परियोजना भारतीय इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गई।

करीब 1,486 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल की कुल लंबाई 1,315 मीटर है। इसके निर्माण में लगभग 28,660 मीट्रिक टन इस्पात का उपयोग किया गया। यह पुल 120 वर्षों की आयु को ध्यान में रखकर बनाया गया है तथा 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं और उच्च भूकंपीय गतिविधियों का सामना कर सकता है।

लेकिन आंकड़ों से कहीं अधिक बड़ी इसकी संघर्षगाथा है। चिनाब घाटी में काम कर रहे इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बदलता मौसम, खिसकती चट्टानें और लगातार होने वाले भूस्खलन। कई बार ऐसा हुआ कि दिनभर का काम कुछ ही मिनटों में ढह गई पहाड़ियों के कारण फिर से शुरू करना पड़ा। पहाड़ों की चट्टानों की परतें लगातार बदलती थीं और हर स्थान की भौगोलिक स्थिति अलग चुनौती प्रस्तुत करती थी।

निर्माण स्थल तक पहुंचना भी किसी अभियान से कम नहीं था। शुरुआत में सामग्री और उपकरणों को दुर्गम पहाड़ियों तक पहुंचाने के लिए खच्चरों और घोड़ों का सहारा लेना पड़ा। बाद में भारी मशीनरी पहुंचाने के लिए विशेष सड़कें बनाई गईं। कई स्थानों पर सड़क ही नहीं थी और इंजीनियरों को खड़ी चट्टानों पर चढ़कर सर्वेक्षण करना पड़ता था।

चिनाब नदी और पहाड़ों का मौसम भी निर्माण कार्य में बड़ी बाधा बना। तेज हवाएं, घना कोहरा, बर्फबारी और बारिश के कारण कई बार काम रोकना पड़ा। नदी के ऊपर सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर स्टील के विशाल हिस्सों को जोड़ना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग कार्यों में गिना गया। भारतीय रेलवे ने पहली बार इतनी ऊंचाई पर विशेष केबल क्रेन तकनीक का उपयोग किया, जिससे दोनों पहाड़ियों के बीच विशाल आर्च को जोड़ा जा सका। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह हाल के दशकों में भारतीय रेलवे के सामने आई सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग चुनौती थी। कठिन भूगोल, भूकंप संवेदनशील क्षेत्र, लगातार बदलती चट्टानों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद भारतीय इंजीनियरों ने हार नहीं मानी और असंभव लगने वाले लक्ष्य को हासिल कर दिखाया।

आज जब चिनाब ब्रिज पर ट्रेन गुजरती है, तो वह केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाती, बल्कि वह भारत की उस क्षमता का संदेश भी दुनिया तक पहुंचाती है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विकास की नई राह बना सकती है। बादलों के बीच खड़ा यह पुल आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि भारतीय इंजीनियरिंग ने हिमालय की कठिन चोटियों पर भी सफलता का परचम लहराया है और विश्व मंच पर एक गौरवशाली इतिहास रचा है।

पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज

नईदुनिया ब्यूरो, अहमदाबादः गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग वाले मामले में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी। अदालत ने उन पर पहले लगाए गए 25 हजार रुपये के जुर्माने को भी बरकरार रखा। यह मामला वर्ष 2016 में शुरू हुआ था, जब केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी।

अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय ने आयोग के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने आयोग का आदेश रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

चलती कार से वर्चुअल पेशी में शामिल हुआ वकील, हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख जुर्माना

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने वाले एक वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने 28 सितंबर को दिए आदेश में इसे नियमों का उल्लंघन बताया। अदालत ने कहा कि वर्चुअल सुनवाई की सुविधा सराहनीय है, लेकिन इसका इस्तेमाल अदालत की गरिमा और कार्यवाही में बाधा डालने वाले तरीके से नहीं होना चाहिए। वकील को जुर्माने की राशि एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि एक दिन में 70 से अधिक मामलों की सुनवाई होती है। ऐसे में सुनवाई के दौरान वाहनों की आवाजाही, पृष्ठभूमि का शोर और अन्य गतिविधियां कार्यवाही में बाधा डाल सकती हैं। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का हवाला देते हुए कहा कि वकीलों को वाहन से सुनवाई में शामिल होने से बचना चाहिए। केवल बेहद जरूरी स्थिति में ही ऐसा किया जा सकता है और इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक है। न्यायमूर्ति शुक्ला ने कहा कि यह प्रावधान केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वकील वर्चुअल माध्यम से भी ऐसी जगह से पेश हों, जहां अदालत की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके। मौजूदा मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी, इसलिए चलती कार से पेशी में शामिल होना नियमों का उल्लंघन माना गया।

पाक ने रोका रूसी विमान का एयरस्पेस बांग्लादेश का परमाणु ईंधन अटका

- रूपपुर परमाणु बिजलीघर के लिए 24 सितंबर को पहुंचना था ईंधन, अक्टूबर में वैकल्पिक मार्ग से होगी आपूर्ति

ढाका/इस्लामाबाद, एजेंसीः बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु बिजलीघर के लिए रूस से भेजा जा रहा परमाणु ईंधन पाकिस्तान द्वारा एयरस्पेस की मंजूरी नहीं दिए जाने के कारण तय समय पर नहीं पहुंच सका। यह खेप 24 सितंबर को बांग्लादेश पहुंचनी थी। ईंधन ले जाने वाले रूसी मालवाहक विमान को अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के रास्ते ढाका पहुंचना था, लेकिन पाकिस्तानी एयरस्पेस की अनुमति नहीं मिलने से आपूर्ति रुक गई। बांग्लादेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फकीर महबूब अनाम के अनुसार, पाकिस्तान ने अनुमति नहीं देने का कारण नहीं बताया था। हालांकि, ढाका स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने इसे उड़ान मार्ग और एयरस्पेस अनुमति से जुड़ी तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्या बताया है। रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम ने अब वैकल्पिक मार्ग से अक्टूबर में ईंधन की आपूर्ति शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए सात मालवाहक उड़ानों के जरिए ईंधन बांग्लादेश पहुंचाया जाएगा और आपूर्ति दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। रोसाटॉम के अनुसार, इस देरी से परियोजना के निर्धारित कार्यक्रम पर असर नहीं पड़ेगा। रूपपुर बांग्लादेश का पहला परमाणु बिजलीघर है, जिसे रोसाटॉम की अगुवाई में बनाया जा रहा है। बांग्लादेश ने बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए रूस के साथ 2011 में समझौता किया था। ढाका से करीब 160 किलोमीटर दूर पद्मा नदी के किनारे इस परियोजना पर 2017 में काम शुरू हुआ था और इसकी लागत करीब 12.65 अरब डॉलर बताई गई है। बांग्लादेश इस समय गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। सितंबर 2026 में कई बार बिजली की कमी 3,500 मेगावाट से अधिक रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 10 घंटे तक बिजली कटौती की स्थिति बनी है, जबकि शहरों में भी दिन में कई बार बिजली कट रही है। अस्पतालों में भी बिजली कटौती का असर देखा गया है। बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था प्राकृतिक गैस पर काफी निर्भर है और गैस आपूर्ति में परेशानी से संकट बढ़ा है। इसका असर परिधान, खाद्य, सिरेमिक और दवा उद्योगों पर भी पड़ा है। ऐसे में रूपपुर परमाणु बिजलीघर को जल्द शुरू करना बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार, सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर 2026 से बिजली उत्पादन शुरू हो सकता है।

बारिश ने तोड़ा 53 साल पुराना रिकॉर्ड, जलस्तर बढ़ने से 833 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया

नईदुनिया ब्यूरो, बस्तरः छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से हुई भारी बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर 53 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। नदी का पानी 12.39 मीटर दर्ज किया गया, जो 9 जुलाई 1973 को दर्ज किए गए 12.18 मीटर के पुराने रिकॉर्ड से 21 सेंटीमीटर अधिक है। जगदलपुर में बाढ़ के कारण कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भी इन क्षेत्रों में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन की ओर से बचाव अभियान चलाया गया। सोमवार को 833 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिले में 65 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां 8,894 लोग रह रहे हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, बीकानेर और चूरू में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम में बदलाव के कारण रात के तापमान में गिरावट आई और शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, उत्तर प्रदेश में सितंबर के महीने में जनवरी जैसा घना कोहरा छाया रहा। अमेठी, रामपुर और बदायूं में मंगलवार सुबह घनी धुंध दिखाई दी। दृश्यता इतनी कम रही कि 25 मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। मौसम में बदलाव के बीच लोगों को हल्की ठंड का भी एहसास हुआ।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान पहुंचा भारतीय दल

इस्लामाबाद, एजेंसीः ऑपरेशन सिंदूर के करीब डेढ़ साल बाद भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में शामिल होने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजा है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और भारत के एससीओ समन्वयक आलोक डिमरी सोमवार से इस्लामाबाद में शुरू हुई राष्ट्रीय समन्वयकों की तीन दिवसीय बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक 30 सितंबर तक चलेगी। इसमें पाकिस्तान की अध्यक्षता में होने वाले एससीओ के कार्यक्रमों, आगामी बैठकों की तैयारियों और संगठन से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा की जा रही है। पाकिस्तान 2026-27 के लिए एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। बैठक के दौरान पाकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मेलन के लिए न्योता दिए जाने की संभावना है।

भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में एससीओ की बैठक में उसकी भागीदारी संगठन से जुड़े विषयों तक सीमित है। भारत एससीओ के मंच पर पाकिस्तान के साथ बहुपक्षीय सहयोग जारी रखेगा, लेकिन दोनों देशों के बीच अलग से द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। भारत का रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए आतंकवाद से मुक्त माहौल जरूरी है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए सैन्य टकराव के बाद भारत ने आतंकवाद और बातचीत को साथ नहीं चलने देने की बात कही थी। इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर अक्टूबर 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने पाकिस्तान गए थे। वह करीब नौ साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री थे। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थीं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी की विवादित टिप्पणी, कहा- श्रीराम अमीरों और शिवजी गरीबों के भगवान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की भगवान राम और भगवान शिव को लेकर की गई टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली में सोमवार को एक मीडिया सम्मेलन में रेवंत रेड्डी ने कहा कि शिवजी गरीबों के और श्रीराम अमीरों के भगवान हैं। उन्होंने भाजपा पर भगवान राम को अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से कांग्रेस दक्षिण भारत में मजबूत है, जबकि उत्तर भारत में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा है। रेवंत रेड्डी ने उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि दक्षिण भारत में लोग शिव की भक्ति करते हैं, जबकि उत्तर भारत में राम की भक्ति अधिक दिखाई देती है। उन्होंने भाजपा के 'जय श्रीराम' नारे का उल्लेख करते हुए पूछा कि पार्टी के नेता 'हर हर महादेव' का नारा क्यों नहीं लगाते। उनके बयान पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई।

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री को भगवान राम और भगवान शिव को उत्तर और दक्षिण के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना के वेमुलवाड़ा और भद्राचलम के धार्मिक महत्व का भी उल्लेख किया।

असर *भारत की बहुस्तरीय कूटनीति की आलोचना करने वाला अमेरिका भी अब कई देशों से रिश्ते साध रहा...*

आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझता अमेरिकाः जयशंकर

न्यूयॉर्क, एजेंसीः विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका के साथ संबंधों और आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं पर कहा कि भारत ने कई दशकों तक पड़ोसी देश की ओर से आतंकवाद का सामना किया है। यदि अमेरिका इसकी गंभीरता को नहीं समझता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ता है। उन्होंने सोमवार को न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में यह बात कही। व्यापार और शुल्क को लेकर भारत-अमेरिका संबंधों में आए तनाव पर जयशंकर ने कहा कि दुनिया के कई देशों के लिए अमेरिका के साथ रिश्ते पहले की तुलना में मुश्किल हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले भारत से अपनी कूटनीति में अमेरिका को अधिक प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन अब अमेरिका खुद रूस, यूक्रेन और चीन सहित कई देशों के साथ संबंध बनाए रख रहा है। उनके मुताबिक, दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां देश किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों के साथ संबंध विकसित कर रहे हैं।

चीन के साथ संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि 2020 में सीमा पर तनाव के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े थे, लेकिन अब सीमा की स्थिति में सुधार के साथ संबंध भी धीरे-धीरे बेहतर हुए हैं। हालांकि, सभी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2024-25 की तुलना में आज स्थिति बेहतर है और सीमा पर जैसे हालात होंगे, दोनों देशों के संबंध भी उसी के अनुरूप रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक ऐसे तनाव में रहना दोनों देशों के हित में नहीं है। वैश्विक स्थिति पर जयशंकर ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, आर्थिक दबाव और व्यापार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिशों से परिस्थितियां अस्थिर हुई हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भी पहले की तुलना में अधिक असुरक्षित हुई हैं। उन्होंने भोजन, ईंधन, खाद और पैसों से जुड़ी चुनौतियों को '4एफ संकट' बताया।

जयशंकर के अनुसार, किसी जरूरी वस्तु के लिए दूसरे देश पर अधिक निर्भरता होने पर उस निर्भरता का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे माहौल में कूटनीति अधिक कठिन हो गई है और राजनयिकों को जोखिम भरे फैसलों के साथ पुराने विवादों को भी संभालना पड़ रहा है। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में कूटनीति को 'एक्सट्रीम स्पोर्ट' बताया।